रूई से कपड़े तक बने राह

उद्योग में बड़े पैमाने पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से ही सार्थक होगा मेक इन इंडिया अभियान

अच्छी फसल बनी कॉटन इंडस्ट्री का सिरदर्द

मनोज मेहता @ इंदौर
business.indore@patrika.com

कॉटन इंडस्ट्री इन दिनों अधिक आपूर्ति (ओवर सप्लाई) की समस्या से गुजर रही है। कपास की फसल रिकॉर्ड स्तर पर होने का का अनुमान है तथा इंडस्ट्री को पूरी उम्मीद है कि बाजार में 3.80 से 4 करोड़ बेल्स तक माल आ जाएगा। दिलचस्प यह है कि इस बंपर फसल के बावजूद कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े तमाम वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स आशंकित हैं। चाहे जिनर हों, जो खेतों से आए कच्चे कपास को प्रोसेस कर रूई और बीज अलग करते हैं या फिर यार्न फैक्ट्री चलाने वाले हों, जो रूई को सूत (यार्न) में बदलकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कच्चा माल मुहैया कराते हैं।

सबके माथे पर आने वाले महीनों में अपने कारोबार को लेकर शिकन है। समस्या के दो मुख्य आयाम हैं, पहला चीन की आयात नीति में बदलाव से कपास के निर्यात में कमी की आशंका और दूसरा गुजरात के लगभग तमाम जिनर्स का अपनी कुल क्षमता के एक छोटे हिस्से पर काम करने को मजबूर होना। हालांकि गुजरात सरकार की नई टेक्सटाइल नीति से उत्साहित उद्योग कम से 80 नई यार्न फैक्ट्रियां लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके बावजूद ओवर कैपेसिटी और बाजार में ज्यादा माल आने की चिंता का असर पहले ही दामों पर दिखने लगा है।

तीस फीसदी नीचे आई कीमतें

पिछले कुछ हफ्तों में कॉटन बेल (356 किलो) की कीमतें लगभग 30 फीसदी लुढ़ककर 33,000 रुपए टन के नीचे आ चुकी हैं और कारोबारियों का कहना है कि बाजार विश्वास के संकट से गुजर रहा है। दामों में इतनी जल्दी आई गिरावट के कारण कई निर्यातकों ने जिनर्स से जो माल उठाया था, उसके भुगतान में पूर्व नियत समय से कई हफ्तों की देरी हो रही है। देश में पिछले साल 3.75 करोड़ बेल (1 बेल में 170 किलोग्राम) कपास का उत्पादन हुआ था।

मध्यप्रदेश में विकास

मध्यप्रदेश अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही देश में टेक्सटाइल का सिरमौर राज्य था तथा यहां की मिलों व कपड़े की ख्याति अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी थी लेकिन सरकारी नीतियों व प्रशासनिक अभाव में 90 के दशक में इसका पतन होना प्रारंभ हो गया। पिछले 10 वर्षों में धीरे ही सही लेकिन इस क्षेत्र में एक बार फिर से सुधार नजर आने लगा है। 10 वर्ष पहले प्रदेश में जहां 5 लाख स्पिंडल कार्यरत थे, वे अब 15 लाख हो गए हैं। पिछले 5 सालों में करीब 15 हजार करोड़ का निवेश टेक्सटाईल क्षेत्र ने हासिल किया है तथा पंजाब की प्रमुख मिलें जैसे नाहर, ओसवाल, ट्राइडेंट ने प्रदेश में अपना विस्तार किया है, जो अच्छे भविष्य के संकेत हैं। अखरने वाली बात यह है कि प्रदेश में अभी भी एक मात्र इंदौर स्थित टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज ही है।

चीनी फेक्टर

भारतीय कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन पिछले साल से ही आयात कम करने की नीतियां बना रहा है, जिससे पिछले साल का बड़ा माल इस साल किसानों के पास स्टॉक में पड़ा है और नया माल बाजार में उतरने लगा है। हमारी कपास की खेती आज पूरी तरह चीन से आने वाली मांग पर निर्भर हो चुकी है लेकिन खतरनाक बात यह है कि चीन का टेक्सटाइल उद्योग बिलकुल भी हमारे कपास पर निर्भर नहीं हुआ है। चीन कपास का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक तो पहले से ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कपास स्टॉकिस्ट भी है। स्वाभाविक है कि इस साल चीन और वियतनाम से आने वाली डिमांड को लेकर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। उसका सीधा असर जिनिंग फैसिलिटीज पर पड़ा है, जो आगे से मांग न आने के कारण अपनी क्षमता से काफी कम पर काम कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो यह एक-तिहाई तक है। यही कारण है कि कपास के दाम में भारी गिरावट आई है।

टेक्सटाइल मंत्रालय बने

चीन की मांग नहीं होने से यार्न रूई के भाव बिकने लगा है। जब तक सरकार गारमेंट व विविंग मिल को बढ़ावा नहीं देगी तब तक स्थिति विकट बनी रहेंगी। मध्यप्रदेश सरकार से हमने अनुरोध किया है कि अन्य कपास उत्पादक राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु की तरह यहां भी अलग से टेक्सटाइल मंत्रालय बनाया जाए। ताकि प्रदेश में यह क्षेत्र तेजी से तरक्की कर अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल कर सके।

अशोक वेदा
सचिव टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया

सरकारी मानसिकता का शिकार

दरअसल समस्या के मूल में हमारी पूर्व सरकारों की मानसिकता है, जिसमें हम दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की जगह तुरत-फुरत मुनाफा बनाने को प्रोत्साहित करते आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे तमाम क्षेत्रों में देश की जो दुर्गति दिखती है, कुछ उसी का साया देश की कपास और सूत इंडस्ट्री पर भी है। समाधान तो तभी होगा, जब केंद्र और राज्य सरकारें कॉटन इंडस्ट्री में बड़े पैमान पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को प्रोत्साहित करें और कपास से सूत और सूत से फैब्रिक का पूरा सफर देश में ही पूरा किया जाए।

नीतिगत प्रोत्साहन नहीं

कई वर्षों से देश का पूरा कपास उद्योग केवल चीन से आने वाली मांग पर निर्भर रहा है क्योंकि हमने धीरे-धीरे देश के टेक्सटाइल उद्योग की हत्या कर दी। अगर हम यह कहते हैं कि पूरा अमेरिकी और यूरोपीय बाजार चीनी टेक्सटाइल से भरा पड़ा है, तो तय जानिए कि उन चीनी कपड़ों में से कई हमारे खेतों में उपजे कपास का उत्पाद हैं लेकिन हमने कभी कपास को सूत में बदलने और उसे टेक्सटाइल में ढालने को नीतिगत प्रोत्साहन नहीं दिया।

भुवन भास्कर
एनसीडीईएक्स